(b) The DDA has reported that during the last 3 years, no loan has been taken from Government. However the details of amount of grants in aid and plan fund received from Delhi Administration during the last 3 years is given below :—

Name of Scheme	Year	Amount
1. Plan Fund		
Innovation & Research :		
	1990-91	10.80 lacs
	1991-92	13.80 lacs
	1992-93	5.00 lacs
	1993-94	Nil
2. *Grants*		
	1990-91	Nil
	1991-92	20.00 lakhs
	1992-93	Nil
	1993-94	Nil

(c) The year-wise break-up of the amount due to DDA from defaulting allottees is not readily available. The amount of hire-purchase instalments yet to be recovered scheme-wise is as under :—

(i) Central Housing Scheme Rs. 1194.00 lacs (as on 31-12-93).

(ii) New Pattern Registration Scheme :

As per the information from DDA an amount of Rs. 16326.00 lacs was recoverable as on 31-3-92 on account of hirepurchase instalments.

(d) The DDA has taken the following steps to recover the outstanding amount :

(i) Issue of defaulter notices.

(ii) Issue of non-recovery certificate under Punjab Land Revenue Act 1887 to recover the outstanding amount as arrears of land revenue.

(iii) Issue of periodical Press/T.V. releases.

(iv) As a follow up to non-recovery certificates, 21 flats of different categories have been attached for non-payment of dues.

(v) There are proposals for advertisement on cable T.V. network.

(vi) Housing Account Management has been recently decentralised zone-wise to monitor recovery of hire-purchase instalments.

दिल्ली विकास प्राधिकरण में नियुक्तियाँ

1746. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में वास्तविक आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों के नियुक्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) और इसके कारण प्राधिकरण को कितना वार्षिक अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं का उचित रूप से उपयोग करके दिल्ली विकास प्राधिकरण पर पड़ने वाले वित्तीय भार को घटाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार प्राधिकरण अपनी वास्तविक आवश्यकता से फालतू किसी भी स्टाफ की नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं करता है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपनी स्टाफ की तैनाती की पद्धति को सरल बनाने और निर्देशानुसार तत्काल किफायती उपाय लागू करने के लिए 21 फरवरी, 1992 को निर्देश जारी किये थे ।

(i) डी०डी०ए० को कहा गया था कि ग्रुप "क", "ख" और "ग" के पदों को न भरें ।

(ii) ग्रुप "ग" के 460 पदों को समाप्त कर दिया गया है।

(iii) ग्रुप "घ" के 550 पदों को वापिस किया जाना है।

(iv) 3500 कार्य प्रभारित स्टाफ स्थानान्तरित किया जाना है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन कार्रवाईयों के कारण डी० डी०ए० के कर्मचारियों की संख्या में यथेष्ट कटौती की गई है :–

(i) आई एस टी टी का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार को स्थानान्तरण ।

(ii) 1992-93 और 1993-94 के दौरान दिल्ली नगर निगम को 282 कलोनियों का स्थानान्तरण ।

(iii) ठेका आधार पर नियुक्त 190 सुरक्षागार्डों की छटनी ।

Better use of rain water

1747. SHRI GOVINDRAO ADIK : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) the number of meteorological regions in the country alongwith the average rainfall region-wise;

(b) how much of this rain water is used for agricultural and energy purposes and how much of it goes waste;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to make a water grid in the country for making the best use of rain water going waste in the interest of getting better agricultural produce and energy production; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) The required information is given in the enclosed statement-I (*See* below).

(b) to (d) The required information is given in the enclosed Statement-II.